'किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने का मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा'

ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राइज़िंग राजस्थान में 28 लाख करोड़ के प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र के हैं

जयपुर, 21 जनवरी। केन्द्रीय रिन्युएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 500 गीगावाट तक बढ़ाने, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य में 5 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाने की प्रक्रिया चल रही है। सभी राजकीय भवनों को सोलर एनर्जी से लैस करने का काम भी प्रगति पर है।**
- **इस समीक्षा बैठक में केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, श्रीपद नाइक तथा हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मंत्रियों व अधिकारियों ने भाग लिया।**

आवश्यकता का 50 प्रतिशत पूरा करने तथा वर्ष 2070 तक देश को नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन तक ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जोशी मंगलवार को जयपुर के एक होटल में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, जारी की है जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें भी 28 लाख करोड़ से अधिक तो अकेले ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन एमओयू से स्थापित होने वाली परियोजनाओं से प्रदेश में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि कुसुम योजना में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। इस योजना में राज्य में 5 हजार मेगावाट से अधिक की सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीकरणीय ऊर्जा पर आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक, राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य में 5 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है और अब तक लगभग 25 हजार घरों पर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सभी राजकीय भवनों को सोलर एनर्जी से लैस करने का कार्य शुरू कर अब तक 489 मेगावाट के एलओए हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर जारी किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि कुसुम योजना के घटक ए एवं सी के तहत प्रदेश में स्थापित विकेन्द्रित सोलर प्लांटों से जुड़े ग्रिड सब स्टेशनों में इन प्लांटों की क्षमता के अनुरूप कृषि कनेक्शन जारी करने का हमने निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली देने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह बड़ा कदम है।

समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंध मंत्री राजेश धर्माणी, जम्मू-कश्मीर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री सतीश कुमार शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर केन्द्रीय सचिव एमएनआरई निधि खरे, केन्द्रीय अतिरिक्त सचिव एमएनआरई सुदीप जैन सहित राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सेना 47 ब्रिज लेइंग टैंक खरीदेगी

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 47 टैंक-72 (ब्रिज लेइंग टैंक बीएलटी) की खरीद के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ 1560 करोड़ रूपये के एक समझौते

- **रक्षा मंत्रालय ने इस खरीद के लिये आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड से 1560 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किये।**

पर हस्ताक्षर किए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में, रक्षा मंत्रालय और हैवी व्हीकल फैक्ट्री और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ब्रिज लेइंग टैंक एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग सेना द्वारा आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के दौरान पुलों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह टैंक और बख्तरबंद वाहनों के बेड़े को अभिन्न पुल बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इससे युद्ध के मैदान में गतिशीलता और आक्रामक क्षमता बढ़ ती है। इस समझौते के अन्तर्गत, खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) होने से रक्षा क्षेत्र में मेक-इन-इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

'यूजीसी दिशा-निर्देश 2025 संविधान की भावना के खिलाफ है'

केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि इसे वापस लें और बदलाव करें

तिरुवनंतपुरम, 21 जनवरी। केरल विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रस्ताव में केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से यूजीसी के दिशा-निर्देश 2025 के मसौदे को वापस लेने और उसमें बदलाव करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि विधानसभा का साफ मानना है कि यूजीसी का मसौदा संविधान की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

गौरतलब है कि जनवरी के पहले हफ्ते में केन्द्र सरकार ने यूजीसी दिशा-निर्देश 2025 का मसौदा जारी किया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस मसौदे का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षिणक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नित को अधिक लचीला बनाना है। हालांकि केरल सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस मसौदे की आलोचना करते हुए कहा था कि वे इसके विरोध के लिए देशभर में गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों को एकजुट करेंगे।

- **केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि दिशा-निर्देश में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति को अधिक लचीला बनाया गया है।**

मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के अनुसार काम करते हैं और राज्यों के पास ही विश्वविद्यालयों की स्थापना और पर्यवेक्षण करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पास केवल उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों के लिए समन्वय और मानक तय करने का अधिकार है। विजयन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इन तथ्यों की अनदेखी करके और सभी हितधारकों से चर्चा किए बिना, दिशा-निर्देश मसौदा जारी किया है। नए मसौदे में कुलपतियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकारों की राय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि यह संघीय प्रणाली और लोकतंत्र के खिलाफ है। केरल के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि नए दिशा-निर्देशों के तहत, अकादमिक विशेषज्ञों पर विचार किए बिना निजी क्षेत्र से भी लोगों को कुलपति नियुक्त किया जा सकता है। सीएम ने आरोप लगाया कि यह उच्च शिक्षा क्षेत्र का व्यवसायीकरण करने की चाल है। विजयन ने आरोप लगाया कि 2025 के यूजीसी मानदंडों के मसौदे को उच्च शिक्षा क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने और इसे धार्मिक और सांप्रदायिक ताकतों के नियंत्रण में देने की कोशिश की जा रही है। विजयन ने प्रस्ताव में कहा, यह सदन सर्वसम्मति से केन्द्र सरकार के 2025 के यूजीसी मानदंडों के मसौदे को तुरंत वापस लेने, राज्य सरकारों और अकादमिक विशेषज्ञों की राय और चिंताओं पर विचार करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने और उनकी राय को गंभीरता से लेने के बाद ही नए मानदंड जारी करने का अनुरोध करता है।

पूरे देश में 26...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डल्लेवाल की भूख हड़ताल का आज 57वां दिन है। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल की देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि शनिवार रात से मेडिकल सहायता लेने के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार है। उनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी।

एआईसीसी में काम-काज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई थी तथा उसे केवल 7 सीटें ही मिली थीं। उसके बाद, पार्टी असम में हारी तथा उसके बाद उसे मध्य प्रदेश में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा।

भँवर जितेन्द्र सिंह, जो गांधी परिवार के सदस्य के रूप में देखे जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह अपरिचित हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, पीसीसी अध्यक्ष के रूप में अपने गृह राज्य हरियाणा जाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि सीनियर हूडा अपना सीएलपी पद छोड़ना नहीं चाहते।

हरियाणा की स्थिति अधर-झूल की बनी हुई है। बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम है कि उनके संबंध में क्या चल रहा है और राहुल गांधी का गला इस समय काफी खराब है तथा उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिये हैं। उन्हें कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उनके स्थान पर पर अब वहाँ प्रियंका गांधी जायेंगी। वेणुगोपाल आज भी पार्टी के वास्तविक "किंग पिन" बने हुये हैं। पार्टी के बहुत से पदाधिकारी उनका दरवाजा खटखटाने के बाद ही संबंधित पदों पर पहुँचे हैं। इनमें तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी से लेकर, अलगा लाम्बा, नीता डी सूजा, देवेन्द्र यादव, काजी निज़ामुद्दीन, नवीन शर्मा, नीरज कुन्दन तक बहुत से नेता शामिल हैं। वेणुगोपाल इस समय पराग शर्मा को हरियाणा में महिला कांग्रेस प्रमुख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान प्रभारी सुखविन्दर सिंह रन्धावा ने कहा है कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाये, लेकिन राजस्थान कांग्रेस आज भी उनके प्रभार में लँगड़ाते हुये चल रही है। जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है, वेणुगोपाल अशोक गहलोत को एआईसीसी में समायोजित करने की कोशिश में हैं। मुकुल वासनिक जैसे बहुत से नेता पार्टी के प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। स्मृति जहाँ तक अतीत में झाँक पा रही है, पार्टी में पुरस्कार और दंड जैसी कोई व्यवस्था नहीं रही है।

समझा जाता है कि अविनाश पान्डे उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ना चाहते हैं, जहां उन्हें प्रियंका गांधी ने नियुक्त किया था। वे शायद कोई और भी ज्यादा लाभप्रद राज्य चाहते हैं। बिना किसी ठोस कार्य योजना तथा इच्छाशक्ति वाले नेता के पार्टी का कायाकल्प एवं पुनरूद्धार कैसे होगा।पहले राहुल गांधी कहा करते थे कि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है क्योंकि पार्टी के कर्ता-धर्ता अहमद पटेल हैं, वे ही पार्टी को चलाते हैं, लेकिन अब तो पार्टी को राहुल गांधी ही चला रहे हैं, तो वे कुछ हट कर क्यों नहीं कर रहे, सार्थक एवं सख्त निर्णय क्यों नहीं ले रहे। प्रियंका गांधी बिना विभाग की महासचिव हैं लेकिन उन्होंने कांग्रेस के हर मामले में अपना पैर फंसा रखा है। सच तो यह है कि वे गांधी परिवार की सदस्य होने के कारण ही ताकतवर हुई हैं। पार्टी में क्या चल रहा है-इस बात को लेकर हर आदमी का ऐसा सोच इसलिए है, क्योंकि इन बिन्दुओं को लेकर न तो पार्टी के पास कोई योजना है और न कोई गंभीर और ठोस विचार और चिन्तन है कि नरेन्द्र मोदी को टक्कर कैसे दी जाये तथा, एक-एक करके, राज्यों में कांग्रेस का कायाकल्प कैसे किया जाये।

'ब्रिक्स देश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति के उपाध्यक्ष हर्ष्री वी. पंत ने कहा कि रुस द्वारा ब्रिक्स मुद्रा के लिए जोर देना, पश्चिमी प्रभाव को कम करने की उसकी व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति के अनुरुप है।

ब्रिक्स देशों द्वारा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के बारे में उठाए गए कदमों की ट्रंप द्वारा की गई आलोचना यू.एस. की बढ़ती चिंता को दर्शाती है, क्योंकि केन्द्रीय बैंकों में अमेरिकी डॉलर के भंडार का हिस्सा बीते दो दशकों में धीरे-धीरे घटा है। यह रुझान, जो शुरु में यूरो के आने से प्रेरित था, अब तेज़ हो गया है, क्योंकि विकासशील देश, जिनमें भारत भी शामिल है, अधिक से अधिक स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। आई.एम.एफ. के आंकड़े बताते हैं कि 1999 में अमेरिकी डॉलर का वैश्विक भंडारों में हिस्सा 71 प्रतिशत था, जो 2024 के मध्य तक घटकर 58 प्रतिशत रह गया है, जबकि यूरो का हिस्सा बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है।

'ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिये जमानत क्यों नहीं दी जाये'

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने एआईएमआईएम के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में अंतरिम या नियमित जमानत देने के सवाल पर दिल्ली पुलिस से अपना पक्ष रखने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि याचिकाकर्ता को 10 में से नौ मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

पीठ ने यह भी कहा कि (हुसैन को) उन्हें धनशोधन के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

याचिकाकर्ता हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि वे चार साल 10 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं। वे फरवरी 2020 तक बेदाग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने यह भी कहा कि कथित हमलावरों सहित, अन्य सभी

- **याचिकाकर्ता को 10 में से 9 मामलों में पहले जमानत मिल चुकी है। सन् 2020 के दंगों के मामले में वह चार साल 10 माह से जेल में बंद है।**

आरोपियों को मामले में जमानत मिल चुकी है।

दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक मामले में हुसैन को कोई राहत नहीं दी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 जनवरी को मामले में अंतरिम जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता रजत नायर से पूछा कि अदालत को याचिकाकर्ता को जमानत या अंतरिम जमानत क्यों नहीं देनी चाहिए?

अमित शाह ने गरियाबंद में 16 नक्सली मारने पर बधाई दी

गरियाबंद, 21 जनवरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ओडिशा सीमा में अब तक 16 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसकी पुष्टि रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के ट्वीट से हुई है। सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर

- **ओडिशा पुलिस मुख्यालय के अनुसार भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारुद बरामद हुआ है।**

ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि इलाके में और नक्सली भी घिरे हो सकते हैं। गरियाबंद में सुरक्षाबल के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ मिली कामयाबी पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों की पीठ थपथपाई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसे गिन रहा है। हमारा अटूट संकल्प है - नक्सल मुक्त भारत, और यह सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की ओडिशा सीमा में गरियाबंद डीआरजी, ओडिशा की एसओजी, कोबरा की 207 बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों ने अब तक 16 नक्सली ढे र कर दिए हैं।

कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी पर दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली कविता सोशल मीडिया पर डालने के मामले में कांग्रेस सांसद एवं कवि इमरान प्रतापगढ़ी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने प्रतापगढ़ी को उनकी याचिका पर यह राहत दी और अदालत ने गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। प्रतापगढ़ी ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने से इन्कार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

प्रतापगढ़ी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज करने की आलोचना करते हुए कहा, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचें ? न्यायालय को कुछ कहना है। बिना नोटिस जारी किए (उच्च) न्यायालय ने इसे (खारिज करने का) आदेश दे दिया।

कांग्रेस सांसद के खिलाफ यह प्राथमिकी एक अधिवक्ता के क्लर्क की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो...' कविता वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। इस मामले में गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ

- **सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा प्रतापगढ़ी की याचिका रद्द करने के संदर्भ में यह आदेश दिया।**
- **प्रतापगढ़ी के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को बिना नोटिस जारी किये खारिज कर दिया।**

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य) और 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द बोलना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। गुजरात उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी को प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है।

अदालत ने कहा, भारत के किसी भी नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा व्यवहार करे जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक सद्भाव बिगड़े नहीं।

सैफ 5 दिन बाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की गई थी।

जैसे ही सैफ अपने घर वापस पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा होने लगे, संभावित रूप से उनके प्रशंसक, मीडिया और शुभचिंतक अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्सुक थे। उनके ठीक होने के बाद, सैफ और करीना ने अपने बच्चों, तैमूर और जेह के साथ बांद्रा में फॉर्च्यून हाइट्स स्थित अपने पूर्व निवास में वापस जाने का फैसला किया है। इस स्थानांतरण का उद्देश्य सैफ के स्वस्थ होने के दौरान परिवार को ज्यादा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

गौतम अडानी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्ञातव्य है कि अडाणी समूह इस साल इस्कॉन और गीता प्रेस के साथ मिलकर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ है। इस्कॉन के साथ मिलकर अडाणी समूह प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण कर रहा है।

कोलकाता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगाए गए हैं। हत्या की सूचना मिलने पर राज्य पुलिस व प्रशासन के इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। मृतक के माता-पिता को मैडिकल कॉलेज ने फोन करके जानकारी दी।

फैसले के साजिश की संभावना बताई गई है तथा पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। फैसले में कहा गया है संबंधित पुलिस स्टेशन के एस.आई. ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं की, यहां तक कि रिकॉर्ड के लिए खाली जगह छोड़ दी थी।

हत्या की प्रारंभिक रिपोर्ट सुबह ही एस.आई. को दे दी गई थी। पर रात 11 बजे तक केस डायरी दर्ज नहीं की गई थी। इसके अलावा पुलिस ने आनन-फानन में ऑटो टैक्सी करवा ली तथा ऐसे मामलों के लिए बने आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया और राज्य प्रशासन माता-पिता की इच्छा का विरूद्ध शव को अंतिम संस्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के केस में मृतका के माता पिता भी शामिल है उनके पास 42 सवालों की लिस्ट है जिनके जवाब नहीं मिले है।

अमेरिका को औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र बनाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केवल लम्बी -चौड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा।

मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करने और बनाये रखने के लिये, प्रशासन को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक निवेश करना पड़ेगा, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल नैटवर्क आदि शामिल हैं। तब जाकर अमेरिका में व्यवसाय करने की लागत कम होगी।

नौकरियाँ वापस लाने के प्रयासों के बावजूद, अमेरिका महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। इस खाई को पाटने के लिये, ट्रम्प प्रशासन को विशाल शिक्षा तथा श्रमिक विकास योजनाओं की जरुरत होगी।

राष्ट्रपति की एकपक्षीय सोच का इतिहास, तथा नाटो, डब्ल्यूटीओ और यूएन जैसी संस्थाओं के प्रति संदेह का नजरिया फिर उभर सकता है। अगर वे अपने मित्र देशों से ज्यादा वित्तीय योगदान मांगेंगे या अमेरिकन हित की खातिर नये गठबंधन करेंगे, तो उनके मित्र देश भी परायापन महसूस करेंगे।

चीन के प्रति उनका तीखा रुख, जिसमें टैक्स तथा महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, अमेरिका और चीन के आर्थिक अलगाव को गहरा कर सकता है। इससे दोनों के बीच भू-राजनैतिक तनाव बढ़ सकते हैं तथा अन्य राष्ट्र किसी एक पक्ष के चयन के लिये बाध्य किये जा सकते हैं।

हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) की पहलों को उलटने तथा जलवायु सम्बंधी समझौतों, जैसे "पेरिस अकॉर्ड," से पीछे हटने की ट्रम्प की संभावना के परिणाम स्वरुप, वैश्विक जलवायु सम्बंधी कार्यों में निश्चित रुप से बाधा उपस्थित होगी तथा अन्य देश भी पर्यावरण सम्बंधी प्रतिबद्धताओं को कम महत्व देने का दुस्साहस कर सकेंगे।

कड़े इमिग्रेशन नियंत्रण और वीज़ा प्रतिबंधों से वैश्विक स्तर पर टैक्नॉलजी और हैल्थकेयर क्षेत्रों के लेबर मार्केट में बाधाएं पैदा होंगी, विशेषकर भारत और मैक्सिको जैसे देशों के लिए।

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। संरक्षणवादी नीतियां कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। इससे वे अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं जो यूएस को निर्यात पर निर्भर हैं, जैसे कि चीन, वियतनाम और मैक्सिको।

बाज़ार, ट्रेड वॉर, आर्थिक विभाजन और नीति की अनिश्चितता के कारण अस्थिरता का सामना कर सकते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी शुल्क से प्रभावित देशों को एक-दूसरे के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं, संभवतः यूएस को अलग करते हुए व्यापार समझौतों में तेजी आ सकती हैं, जैसे कि रीजनल कॉम्प्रिहैन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप।

ई.यू., असियान और लैटिन अमेरिकी देश यूएस संरक्षणवाद से बचने के लिए अधिक क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। वाइट हाउस में ट्रंप के आने के बाद, यूएस-चीन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है। ट्रंप का चीन पर कठोर रुख तनाव बढ़ा सकता है, जो ग्लोबल ग्रोथ और व्यापार प्रवाह को प्रभावित करेगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव हो सकता है कि वे यूएस या चीन में से किसी एक के साथ गठबंधन करें, और इससे उनकी विदेश नीति आर्थिक रणनीतियों में जटिलता पैदा हो सकती है।

एक नया जिओपोलिटिकल समीकरण भी संभव है। यूरोप और एशिया के पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी ट्रंप की अनिश्चितता से बचने के लिए क्षेत्रीय पार्टनरशिप को गहरा सकते हैं। रुस और चीन, मध्य पूर्व, अफ्रीका और मध्य एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं।

जहाँ तक ऊर्जा बाज़ारों का प्रश्न है जलवायु समझौतों से यूएस के बाहर जाने की संभावना और जीवाश्म ईंधन पर नया फोकस वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को कमजोर कर सकता है। तेल निर्यातक देशों को, नवीकरणीय ऊर्जा में अमेरिका की घटती भूमिका का फायदा हो सकता है, लेकिन भू-राजनीतिक तनावों के कारण मूल्य अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है।

ट्रंप की नीतियां ग्लोबल टैक इकोसिस्टम प्रणालियों के खंडित होने का कारण बन सकती हैं, क्योंकि कई देशों ने टैक्नॉलजी पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में समानांतर प्रणालियां विकसित की हैं और अंत में अमेरिका -चीन प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के तेज होने के कारण विकासशील देशों को सस्ती टैक्नॉलजी तक पहुंच बनाने में कठिनाई हो सकती है।

ट्रंप की नीतियों में वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता है। जहाँ, कुछ देशों को यूएस द्वारा छोड़े गए आर्थिक और रणनीतिक खाली स्थान से लाभ हो सकता है। अन्य देशों को आर्थिक व्यवधानों और बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनावों का सामना करना पड़ सकता है।

संकल्प पत्र-2 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक मुफ्त शिक्षा देंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15 हजार रूपए देंगे। । पार्टी ने दिल्ली में ऑटो-टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाने तथा ऑटो-टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और पांच लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का वादा किया है।

ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है और डीबीटी के माध्यम से जन-कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की है।

हमारी सरकार बनने पर हम स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी और परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे। दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने का प्रयास करेंगे।

भाजपा ने कामगारों के लिए डोमेस्टिक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही है। इसके 10 लाख रुपये का जीवन बीमा, 05 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 06 महीने की पेड मैटरनिटी लीव देने का किया गया है।

'केवल अमेरिका में पैदा होना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बच्चों को अमेरिकन नागरिक माना गया था।

वर्ष 1898 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अगर चीन के दम्पती की संतान अमेरिका में जन्म लेती हे तो वह नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी है।

ट्रम्प के आदेश के अनुसार, अगर अमेरिका में जन्मे बच्चों के माता-पिता अमेरिकन नागरिक नहीं हैं तो उन्हें भी अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि 14वें संशोधन की गलत व्याख्या की गई है।

ट्रम्प के आदेश में कहा गया है कि, चौदहवां संशोधन यह नहीं कहता है कि अमेरिका में जन्में सभी लोगों के अमेरिकन नागरिकता मिलेगी। इस संशोधन में अमेरिका में जन्मे लोगों को जन्म आधारित नागरिकता की बात नहीं की गई थी, बल्कि उसे क्षेत्राधिकार के दायरे में रखा गया था।

हालिया जनगणना के अनुसार, अमेरिका में 54 लाख से अधिक भारतीय हैं, जो अमेरिकी आबादी का लगभग 1.47 प्रतिशत हैं। इनमें से दो-तिहाई अप्रवासी हैं, जबकि 34 प्रतिशत अमेरिका में जन्मे हैं।

अगर ट्रम्प का कदम लागू होता है तो अस्थायी कार्य वीज़ा या पर्यटक वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी।

कार्यकारी आदेश का उद्देश्य देश में "बर्थ टूरिज़्म" करना भी है। इसमें एक महिला अमेरिका जाती है और वहाँ बच्चे को जन्म देती है, जिससे अधिकारिक आंकड़